[श्री शिव चन्द्र झा]

Everyone hag the duty to work and the right to obtain employment... every human being who, because of his age,, his physical or mental conditions, or because of economic situation[1], finds himself unable to work, has the right to obtain from the community the meang to lead a decent existence. The nation guarantees Equal acess of children* and adults to education professional training and culture.

58 का जो रिपब्लिक कांस्टिटुयुशन फ्रांस का है उसमें उसने इसको री-अफिम किया है । लीबिया के संविधान में भी यह है ।

श्री उपसभापति : झा जी, यह बहस आप लंच के बाद जारी कर सकते हैं ।

SHRI SHAHABUDDIN: Introduction of Bill.

THE CONSTITUTION (AMEND-MENT BILL

, 1982 (to amend articles 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 and 323)

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): I beg to move for leave to Introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question *was put and the motion was adopted.*

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to make a few announcements. The discussion *ore* the Private Members' Bills will continue upto 4.30 and we shall take up at 4.30 the Calling Attention Motion. The hoir. Prime Minister will make a statement at 5 P.M.

सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Shri Sat Paul Mittal) in the Chair.

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Congratulations to the *itew* Vice-Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRTt SAT PAUL MITTAL): Thank you Shri Shiva Chandra Jha to continue.

THE CONSTITUTION (AMEND MENT) BILL, 1978

(Insertion of new Article 1<5A) —*contd.*

ती शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष जी, लंच के पहले मैं बोल रहा था अपने संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर जिसमें कि मैं प्राविधान करवाना चाहता हूं कि राईट टु वर्क फण्डामेंटल राईट के रूप में लिखा जाय । उस पर बोलते हुए मैं बोल रहा था लंच के पहले कि अभी की परिस्थिति में भी दुनिया में ऐसे मुल्क है जहां के संविधान में जिन के संविधान में राईट टु वर्क लिखा हुआ है, सविधान में गारण्टिड है । मैंने नाम पढ़कर सुनाये ये मुल्क हैं, बोलीविया, बल्गरिया; लीबिया, अल्बानिया, चाईनां चेकोस्वोवा-किया, वेनेजुएला, नार्थ वियतनाम, पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ यमन, यूगो-स्लाविया, मंगोलियन पीपुल्स रिपब्लिक, जापान, नार्थ कोरिया, पोलेण्ड, रूमानिया, सीरिया, यू० एस० एस० आर0, ईराक, हंगरी । यहां राईट टु वर्क गारण्टिड हैं । कुछ ऐसे भी मुल्क हैं, दुनिया में जहां अनइम्प्लायमेंट बेनीफिट गारण्टीड है यदि काम नहीं मिलता है सरकार काम नहीं दे पाती है या नहीं है तो कम से कम

बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं, उसका प्रावधान है उनके संविधान में । वे मुल्क हैं आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, बेलियम, बोलीविया ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलम्बिया, क्यूबा, डेनमार्क, डोमनिकन रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस, जिब्राल्टर, हान्डुरास, इटली, आयरलैण्ड, जापान, लक्जमबर्ग, मदरलेण्ड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, स्पेन, स्विटरजरलैंड, ट्रिनीडाड, टुबेगो । ये मुल्क है जहां अनइम्प्लायमेंट भत्ते का प्रावधान है । अभी के सेटअप में उन मुल्कों के नाम मैंने बताए जो कांग्रेस ब्लाक में कहते हैं, उन की व्यवस्था एक है और मैंने बताया, वहां की व्यवस्था एक होने से कहा जा सकता है कि वहां पर राइट टु वर्क संभव है। अब मैं यू एस एस आर० का जो कांस्टिट्यूशन का आर्टिकल है वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । उस से पता चल जाएगा दूसरे कम्युनिस्ट मुल्कों के बारे में । आर्टिकल 118 यू० एस० एस० आर कांस्टिट्यूशन का कहता है--

"The citizens of the USSR shall have the right to work, that is, the right to guaranteed employment and payment for their work in accordance with its quantity and quality..."

तो कम्युनिस्ट ब्लाक के जितने मुल्क है, मोटे तौर पर उसी पैटर्न पर हैं । इस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है । जापान उसमें नहीं आता है । उसके आर्टिकल 27 में है--

"All people shall have the right and obigation to work. Standards for wages, hours, rest and other working Conditions shall be fixed by law..."

इसी तरह से मैं पढ़ रहा था लीबिया के बारे में लीबिया के कांस्टिट्युशन में आर्टिकल 4 कहता है कि--

"Working in Libyan Arab Republic is a right, a duty and honour for everv abU bodies citizen..."

तो ये ऐसे मुल्क हैं जो कि कम्युनिस्ट छत्रछाया में नहीं है, जो थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं तथाकथित फ्री वरल्ड में है । लेकिन उनके संविधान में भी लिखा हुआ है, राइट टु वर्क गारण्टीड है । आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि लीबिया में कहां फुल इम्प्लायमेंट है ? कुछ लोग खोज कर बता सकते हैं कि वहां अन्इम्प्लायमेंट है । हम मान सकते हैं, कुछ ऐसे अन्इम्प्लयीड होते हैं । जैसे कि मान लीजिए कोई कारखाना है, बंद हो गया, कारखाना क्लोज कर दिया गया, यहां का कारखाना दूसरी जगह उठा कर ले गए, तो जो मजदूर काम करते हैं उनके एडजस्टमेंट में दस-पन्द्रह बीस दिन या दो महीने की देरी हो सकती है । तो इसको आप अन्इम्प्लायीड का रूप दे सकते हैं । इस तरह आप उन मुल्कों की खोज करके जहां संविधान में यह एक गारण्टीड राइट है उसको निकाल सकते हैं । लेकिन यह सेकेण्डरी बात है । अहम बात यह है कि संविधान का जो आदेश है उस में कोई नागरिक बेकार नहीं रहेगा । जो काम करने की क्षमता रखता है और काम करना चाहता है, काम खोजता है, उसको सरकार लाजमी तौर पर काम देगी । यदि सरकार काम नहीं देती है तो सरकार बाहर कैसे कर देगी और अगर वह कोर्ट जाएगा तो कोर्ट रिट देगा और इंजेक्शन देगा कि सरकार काम दे । काम नहीं देगी तो सरकार भत्ता दे । अब इस संदर्भ के बाद हम आ गए अपने मुल्क में ? तो यहां क्या किया जाए ? मैंने पढ़ कर बताया कि--मेरा संविधान संशोधन है जो फण्डामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल 16-ए जोड़ने के बारे में है। मैंने यह भी कहा कि 39 और 41 में जो डाइरेक्टिव प्रिंसिप्लस हैं उन में इस तरह की बातें हैं, अन्इम्प्लायमेंट के बारे में जैसे इकानामिक सिटस्म जब प्रोवाइड करें

[श्री शिव चन्द्र झा[

तब लेकिन वह मेंडेटरी नहीं है । इसी लिए डाइरेक्टिव प्रिंसिपल की बात उतनी जोरदार नहीं होती है । फण्डामेंटल राइट को राइट टु वर्क के साथ जोड़ते हैं तो उसका मतलब दूसरा होता है । संविधान के जरिए दूसरा मतलब होता है और जनतंत्र में ज्यादा मतलब यही हो जाता है । इस परिस्थिति को लाने के लिए दलील दी जाती है कि सरकार काम कहां से देगी, इतने लोगों को काम देने के लिए पैसा कहां से आयेगा । इस समस्या का विकराल रूप दिखाई देता है जब बेरोजगारी की समस्या हमरे सामने रखते हैं । कितने लोग बेकार हैं? क्या सरकारी आंकड़े हैं? आप बताइये सही आंकड़े क्या हैं । पहले तो सरकार आंकड़े देने से ही कतराती है, भागती है क्योंकि यह समस्या बहुत जोरदार समस्या होती जा रही है । चारों तरफ इस की ज्वालाएं फूट रही हैं । आज देश में जो गड़बड़ियां हम पाते हैं आसम से लेकर गुजरात तक या काश्मीर से कन्याकुमारी तक, सब की जड़ में यही है, चाहे उस का रूप हिंसा का हो, चाहे जोर-जुल्म का हो । हमारे नौजवान बेकार हैं । आइडिल माइंड इज डेविल्स वर्कशाप खाली मन शैतान का घर है । काम कुछ नहीं है तो जो मन में आता है वह करेंगे । खुराफात की फिजा इस से पैदा होती है । ऐसे कितने अनएम्प्लाएड लोग हैं । क्या सरकारी आंकड़े चार करोड़ से ज्यादा हैं । मैं गलत हूं तो आप बताईये । प्लानिंग कमीशन की कन्सलटेटिव कमेटी में भी यह बात मैंने रखी । वहां भी मैंने बात उठाई कि उस के सही आंकड़े क्या हैं । पहले तो सही आंकड़े से यह कतराते हैं क्योंकि उस में पकड़े जावेंगे रंगे हाथ । हर योजना के बाद, पहली पंच-वर्षीय योजना से लेकर अब तक बेरोजगारी की समस्या बढ़ती गयी है । मैं मानता हूं कि कुछ कारखाने बने हैं, कुछ उद्योग लगे हैं, कुछ रोजगार नये बने हैं, लेकिन बेरोजगारी का रूप बढ़ता गया है । जितनी रोजगारी बनायी गयी है उस से ज्यादा हर योजना के आखिर में बेरोजगारी बढ़ी है । अब छठी योजना के बीच से जब हम गुजर रहे हैं तो बेकार लोगों की संख्या चार करोड़ से ज्यादा है । आप कहें दो करोड़ है तो मान लीजिए दो ही करोड़ आप ही की बात सही । उस से कम कहें तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वही सही है । डेढ़-दो करोड़ से ऊपर लोग बेकार हैं । हर ब्लाक में एक हजार आदमी को मेनुअल वर्क की योजना आप चला दीजिए । 5005 ब्लाक है सारे देश में । एक हजार आदमी प्रति ब्लाक में बहाल किए जायं तो 5005 ब्लाक का हिसाब आप लगा लें । यह देहाती वेल्ट है, एग्रीकल्चरल इन्टीरियर है । वहां पर ऐसे लोगों को प्रति महीने 200 रुपए देने की योजना बना कर बांध बनाने, डैम बनाने, गड्ढे भरने और सड़क की सफाई करने जैसे काम लें । आप को आश्चर्य होगा अमरीका पूंजी-वाद का घर है, विकसित देशों में गिना जाता है । 1929 में जब वाल स्ट्रीट क्रेश हुआ था, जब बड़ा संकट आया था, अमरीका में हाहाकार मच गया था, नौजवान सड़कों पर मारा-मारा फिरते थे । हुवरप्रेसिडेंट थे, लेकिन लोगों ने हुवर को फेंक दिया । एफ॰डी॰आर॰ ने कहा कि वह राष्ट्र जिन्दा नहीं कहला सकता यदि उस के नौजवान सड़कों पर मारे-मारे फिरे । लोग अमरीकी संविधान की दुहाई देते थे । उसने कहा कि संविधान को हम चाटेंगे, उस में कहा है कि स्टेट एन्टरप्राइज न हो, संविधान को हम चाटेंगे?

जब बागडोर उस के हाथ में आयी तो उस ने एक नयी नीति शुरु की । सी॰सी॰ कैंप्स खोले । नौजवानों को लकड़ी काट

कर काम देना शुरू किया। टेनिसन वैली प्रोजेक्ट बनाया। स्टेट नये-नये काम करे और लोगों को इंप्लायमेंट दे इस के लिये उस ने रास्ते निकाले। मुल्क में सड़क बनाने आदि का काम दे कर उस ने लोगों को रोजगार देने की शुरुआत की। तो वहां की अर्थ व्यवस्था जो दम तोड़ रही थी वह फिर दम पकड़ने लगी और जिन्दा होने लगी। वहां ऐसा हुआ। क्या आप भी हर ब्लाक में एक हजार नौजवानों को काम देंगे। आज देहात में जा कर देखें। मंत्री जी, आप तो बिहार के लाट साहब रह चुके हैं। पांच साल तक वहां आप ने लाट साहबी की है। मैं उत्तरी बिहार, मधुबनी से आता हूं। आप रहिता भी गये हुए हैं। आप सोचें कि वह इलाका कितना पिछड़ा हुआ है। बरसात के दिनों में आप मधुबनी से मेरे घर तक नहीं जा सकते हैं। मैं जब जाता हूं और अब बरसात शुरु हो गयी तो लुंगी साथ में रखता हूं। मधुबनी से इधर ही भंगोड़ा है वहां कपड़े उतार कर लूंगी पहन लेता हूं। एक नदी है जीवस उस में इतना पानी आ जाता है कि वहां कोई रास्ता नहीं बचता। और जब अपने घर दरवाजे पर पहुंच जाता हूं तो लुंगी उतार कर अपने दूसरे कपड़े पहन लेता हूं। फिर मधुबनी आना होता है तो लूंगी पहन कर बाकी कपड़े झोले में रख कर पानी में चल कर आता हूं और फिर पानी पार कर के, आधे घंटे 45 मिनट बाद फिर कपड़े पहनता हूं। तो वहां की यह परिस्थिति है। क्या यह बात आप को याद है या नहीं। आप इस पानी को रोक सकते हैं या नहीं। इस नदी पर बांध बनाने के लिये एक भीमा स्कीम वहां की है लेकिन वह खटाई में पड़ी हुई है। जगन्नाथ मिश्र जी कि फाइलों में वह है या वह उस को खा गये इस का पता नहीं है। तो ऐसे बहुत से काम हैं बिहार में और हिन्दुस्तान में कि जिन को आप उन नौजवानों के हाथ में, जिन के हाथ में ताकत है दे कर करवा सकते हैं। उन को उस के लिये दो सौ रुपये प्रति माह के हिसाब से देना शुरू कर दें या एन सी सी में हम यह काम शुरू करा दें तो यह बहाल हो जायेंगे और एग्रीकल्चरल एरिया में जितनी बेरोजगारी है उस को समाप्त करने के लिये यह शुरुआत की जा सकती है। पैसा आप को लगाना होगा और हर नौजवान को दो सौ रुपया प्रति माह देना होगा और हर ब्लाक में आप एक हजार नौजवानों को काम दीजिए और फिर पांच ब्लाक को आप जोड़िये तो देखिये कि कितना लगता है। मैं ने इस का थोड़ा-सा हिसाब किया है। कुल 15 सौ करोड़ रुपया लगता है। शायद यह 12 या 13 सौ करोड़ रुपया ही होता है। तो क्या यह काम आप के लिये असंभव है? क्या यह हिन्दुस्तान की सरकार के लिये असंभव है? इस में टाउन का भी इंप्लायमेंट का सवाल है, लेकिन इस समय देश के सामने जो वर्निंग समस्या है उसी को मैं उठा रहा हूं। क्या 12, 13 सौ करोड़ रुपया हर साल खर्च कर पाना इस सरकार के लिये मुश्किल है। देश में पैसा है। यह किया जा सकता है। कहा जाता है कि आज भारत गरीब है। बिलकुल गलत बात है। भारत गरीब नहीं है। भारत की जनता गरीब है। भारत की जनता गरीब नहीं है, भारत की जनता गरीब बनायी गयी है। भारत में इतनी दौलत है कि उस से यह सारा काम किया जा सकता है। यदि आप के दिल में बुलन्दी हो और आप में हौंसला मौजूद हो तो आप इस को सोने की दुनिया बना सकते हैं। लेकिन 14 साल के बाद जो आप की नीति रही है उस में गरीब और गरीब हुआ है और अमीर और ज्यादा अमीर हुआ है। कहा जायगा कि आप की योजनायें बड़ी हैं। आप तो

[श्री शिव चन्द्र झा]

कानून मंत्री हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या टाटा, बिड़ला बड़े नहीं हैं ? टाटा, बिड़ला और मोनोपली हाउसेज बड़े हैं आपकी योजनाओं को बदौलत । आप क्या करने जा रहे हैं उनको रोकने के लिये ? क्या उनको आप नेशनलाइज करेंगे ? कम से कम 20 मोनोपली हाउसेज आप नेशनलाइज कर लें तो बड़े-बड़े मगरमच्छ आपके काबू में आ सकेंगे । आप कहेंगे नेशनलाइज करने से क्या होता है । यही तो रोग है सरकार और इस प्रशासन में । जहां कोई नई बात रखी जाए, बुनियादी बात रखी जाए, क्रांतिकारी परिवर्तन वाली बात रखी जाए तो सरकार को इधर उधर करने लगते हैं । मंत्री जी आप पता नहीं कहां थे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, प्रिवी पर्स का खात्मा किया गया है । आप कहां थे उस वक्त । वह काम भी खराब मालूम होता था । असंभव समझा जाता था । हम लोग उस समय फोर्थ लोक सभा में थे । वह समय ऐसा था जब हम लोग सदन में हल्ला करते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, प्रिवी पर्स का राष्ट्रीयकरण करो । उसका खात्मा करो और वह विद-आउट कंपेंसेशन किया गया तो सब लोग ढोल पीटने लगे कि बड़ा अच्छा काम हुआ । मोनोपली हाउसेज का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो सब ढपली बजाने लगेंगे कि बड़ा अच्छा काम हुआ है । लेकिन अब वक्त का तकाजा है कि बिड़ला और टाटा का आप राष्ट्रीयकरण करें । हम मानते हैं कि पब्लिक सैक्टर में खराबियां हैं, लेकिन वह अशोक पथ है, समाजवाद की ओर जाने के लिए । यह ख्याल दिमाग से हटा लें कि राष्ट्रीयकरण करना यूजफुल स्लोगन है कि जोश में आकर कह दिया । मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी और रास्ते पर न चलें । पंडित जवाहरलाल जी ने लिखा है और खासकर तीसरी पंचवर्षीय योजना के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि वह क्लासिकल डाक्यूमेंट है उसी पर आप चलें तो बहुत कल्याण हो जाएगा लेकिन आप उस पर जायेंगे नहीं । आपका तो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसी का ढोल पीटना है जिसमें है तो कुछ नहीं एक भानमती का कुनबा है जिसमें सब जोड़कर रखा गया है ।

तो मैं उपाध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि यदि सरकार की इच्छा हो जाती है तो पैसे आ जायेंगे । आपके देखते-देखते आ जायेंगे । अक्टूबर 1962 में आपने देखा कि चाइनीज ऐग्रेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब ऐलान किया तो सोना घरों से निकलने लगा । मध्यवर्ती में मैंने भी दिया था कुछ जब वहां पर मीटिंग हुई थी । सुबह होते-होते घरों से सोने के जेवरात निकलने लगे थे । आप आह्वान करेंगे तो पैसे घरों से निकलने लगेंगे । आप नेशनलाइज करके तो देखिये । टाटा, बिड़ला कांप्लैक्स को आप नेशनलाइज करेंगे तो दौलत आपके कदमों पर आ गिरेगी । लेकिन आपकी भावना नहीं है । आपकी सांठ-गांठ है उनके साथ और चुनाव में या दूसरे वक्त आपको पैसे मिलते हैं उनसे । लेकिन यह इतिहास का तकाजा है । आपके हाथ पकड़कर वह आपसे करवायेगा । आप नहीं होंगे तो दूसरे होंगे तीसरे होंगे । तकाजा है सोशल सेक्टर का पब्लिक सेक्टर पर सोशल आनरशिप का क्योंकि देश समाजवाद मांगता है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मैंने कहा कि हर ब्लाक में एक सैल्फ इंप्लायमेंट की नीति बनाई जाए । 5005 ब्लाक हैं आपके लगभग 1500 करोड़ या 1800 करोड़ रुपये इस पर लगते हैं । आप इकानामिक पालिसी ठीक कर लेते हैं तो आपको पैसे आ जायेंगे ।

इनकम सीलिंग की बात जहां तक है उसको आप एक और दस के अनुपात में करें उसकी हदबंदी करें। उसकी हद बन्दी लाकर आप देखिए कि कितने पैसे आपको आते हैं। एक शख्स है जिसने हिसाब दिया था वह थे डा० राम राम मनोहर लोहिया। उन्होंने कहा था कि इसको लागू कर दिया जा तो एक हजार करोड़ रुपये की आमदनी होने लगेगी। कोई ऐसा इन्कलाब करने से एक हजार करोड़ रुपया आपके पास आ जायेगा। प्रधान मंत्री के ऊपर कितना खर्च होता है हिसाब देख कर आप बताइये। डा० लोहिया ने उस प्रधान मत्री के बारे में हिसाब किया था जब कि पैसे का मूल्य बहुत ज्यादा था। आज कम से कम लाख रुपया रोज प्रधान मत्री पर खर्च करते होंगे।

श्री पी० एन० सुकुल (उत्तर प्रदेश) : इतना ही जब मोरारजी देसाई प्रधान मत्री थे, उन पर खर्च होता था। चौधरी चरण पर खर्च होता था।

श्री शिव चन्द्र झा : जब मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे उन दिनों आप भी थे राज्य सभा में। हम लोग वहां बैठते थे जहां आप हैं और शायद आप इधर बैठते थे। वहां से हम लोग क्या बोलते थे यह शायद आप जानते होंगे। हम लोगों ने बहुत जोर दिया। हमारा रेजौलुशन था।

श्री पी० एन० सुकुल : आपके बोलने का नतीजा क्या हुआ।

श्री शिव चन्द्र झा : यदि उन्होंने नहीं किया, चरण सिंह ने नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी न करें। अगर वह गिरते हैं यह नहीं कि आप भी गिरें। यह तो नहीं होना चाहिए कि वह कुए में गिरे तो आप भी कुए में गिरे। यह गांधी का देश है। हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करना गांधी के देश की बात नहीं है। मेरा यह कहना है कि यदि आप इकोनोमिक सीलिंग लगायें तो एक हजार करोड़ रुपया आप आसानी से ले सकते हैं। अमेरिकी शास्त्री का हिसाब है कि पांच सौ करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। टेक्स इवेजिन की बात आती है। कलडार रिपोर्ट के आंकड़े आपके पास होंगे। उसके हिसाब से 300–400 करोड़ रुपया आ सकता है। वांचू कमेटी की रिपोर्ट को ले लें तो 1400 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया वहां से आ सकता है। ब्लैक मनी को अगर आप सख्ती से मोबोलाइज कर लें तो 1500 करोड़ रुपया साल भर में आ जायेगा। आपके पास पांच हजार पांच ब्लाक हैं आप उसमें नौजवानों को काम पर लगायें। होडर्स की बात है उस पर भी कट्रोल करें। खाली प्रतिभा प्रतिष्ठान में ही नहीं पैसा है सारे मन्दिरों में पैसा भरा पड़ा है। मस्जिदों में तो नहीं है पैसा लेकिन मन्दिरों में मूर्तियों में सोना भरा पड़ा है। देश में कितना पैसा जमा है उसको आप अर्थ करें।

डा० रफी जकरीया (महाराष्ट्र) : जरा आइस्ता बोलिये कान फट रहे हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : आपके कान फट रहे हैं तो आप निकल जाइये। इस देश में कितना धन जमा है अगर हिसाब लगाया जाए तो 50 हजार करोड़ से कम नहीं है। मन्दिरों में और बड़े-बड़े घरानों में पैसा भरा पडा है। आप इनके मोबोलाइज करिये। महाराजा दरभंगा का नाम आपने सुना होगा। उत्तरी बिहार में है। आप लाठ साहब थे वहां पर आपने सुना होगा। चाइनीज अग्रेशन के बाद सात मन सोना दिया था। मैं तारीफ के रूप में नहीं कहता। मैं हकीकत में

[श्री शिव चन्द्र झा]

कहता हूं सात मन सोना दिया गया। एक छोटा सा जमींदार सो क्राल्ड महाराजा अभी भी उसके पास बहुत सा है। मालूम नहीं कब खत्म होगा। इस सारे देश में अब्दुल रहमान अंतुले के खजाने में ही नहीं दूसरे खजानों में भी पैसा जमा है। उसने तो बड़ी सफाई से हथा मारा लेकिन जगन्नाथ मिश्र 7 करोड़, 8 करोड़ रुपया लेकर काठमांडू जा रहे थे। यह हकीकत है। उनको बार्डर पर रोका गया। यह आपकी क्या हकूमत है जो 3 p.m. हर जगह गड़बड़ी करती है ? मैं सारी बातों को नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ यह कहना चाहता हू कि आपकी हुकूमत हर जगह गड़बड़ी करती है (**समय का घंटा**) मैं खत्म कर रहा हू। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो पैसे को मोबेलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बातें मैंने कही हैं उनसे आप पैसा मोबेलाइज कर सकते हैं। यह जो राइट टू वर्क की बात है इसको संविधान में, कानून में, लाना चाहिए। आप कहेंगे कि इतने आदमियों के लिए कैसे इंतजाम हो सकता है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हू कि यह काम पांच मिनट में हो सकता है और पांच मिनट में अनइम्प्लामेन्ट खत्म हो सकता है। लेकिन इसके लिए इम्प्ली-मैन्टेशन की बात आती है। जब इम्प्ली-मैन्टेशन की बात आती है तो यहां पर बात अटक जाती है। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो, भावना हो, तो सभी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। सुनिश्चित जनतंत्र के लिए, सुनिश्चित डेमोक्रेसी के लिए संविधान में इस प्रकार का संशोधन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप हर तरह से इस पोजीशन में हैं। मैं कोई रेडिकल चैन्जैच की बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर पैसे की गारण्टी हो जाती है तो फिर भी क्या आपको इस पर एतराज होगा ? मैं समझता हू कि अगर पैसे की गारन्टी हो जाती है तो आपको इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। पैसे की वजह से आप इसको मत रोकिए। पैसे का इंतजाम हो सकता है। आप यह कह सकते हैं कि इतने अनइम्प्लाइड लोगों के लिए पैसा कहां से लाए। अगर इस तरह से सब के लिए पैसे का इंतजाम किया जाएगा तो यह रोग बढ़ सकता है, यह भी आपका कहना हो सकता है जहां तक पोपुलेशन कंट्रोल का सबध है, वह एक अलग सवाल है। उसमें भी आपने गड़बड़ी कर रखी है। बुनियादी बात यह है कि आपका जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। अगर आपको देश को इंडस्ट्रेलाइज करना है तो आपको अपनी नीति में बुनियादी परिवर्तन करना होगा। भारत क्यों पिछड़ गया क्योंकि उसने मार्डन टैक्नोलोजी को भुला दिया। शोयालयी इकमोमी को आपको छोड़ना होगा। मैं आपकी पालिसी को शोचालयी इकनोमी कहता हूं। आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की टैक्नीक को छोड़ना होगा और मार्डन टैकनीक पर चलना होगा। हमें हिन्दुस्तान को चांद पर उतारना है। हम अनटार्टिका में पहुंच गये। वहां पर हम जिस जहाज पर गये, यद्यपि वह नार्वे का था लेकिन उसमें हमारे देश के लोग थे। जब हमें यह समाचार मिला तो हमने खुशियां मनाई। जब हमें स्पेस में भी जाना है। रीगन ने कहा है कि स्पेस का नया फ्रंटियर खुला है। अमेरिका में फ्रंटिचर का एक अलग दर्शन है। भारत दुनिया के इतिहास में इसलिए पिछड़ गया था कि उसने माडर्न टैक्नोलोजी को भुला दिया। इसलिए आज जरूरत इस बात है कि कि माडर्न टैक्नोलोजी को अपनाया जाय। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। आज हमारे यहां पर नये टक्नोलोजी की बात कही जा रही है। कलर टी० वी० की

बात भी कही जा रही है। हम अपनी गरीबी और बेरोजगारी से तब तक छुटकारा नहीं पा सकते हैं जब तक हम नई नई टैक्नीक नहीं सीखते हैं। हमारा यह दर्शन है कि हम अप टु डैट रहे। हमको देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है और इसके नतीजे के लिये हमको इस क्षेत्र में परिवर्तन करना होगा। यह एक अलग विषय है जिस पर मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन असल में मोनोपली हाउसेज को जो बढ़ावा दिया जाता है वह क्यों दिया जाये? एग्रीकल्चर सैक्टर इम्पलाईमेन्ट और लैण्ड रिफार्म की अपनी एक अलग कहानी है। इस तरह से हम देखते हैं कि देश में पैसा तो है। पैसा इसके लिये होना चाहिये और संविधान में संशोधन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिये इस दृष्टि से जो सिचुयेशन है वह बिल्कुल दुरुस्त है। उपसभाध्यक्ष महोदय, राइट टु वर्क इसको देश आपसे मांग रहा है। आप भी 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करते हैं। क्या है यह? क्या है यह बतलाइये? इसमें क्या है मतलब वाली बात? तो क्या इसमें अनइम्पलाइमेन्ट को दूर करने की बात नहीं है? क्या ऐसा करने से आपके 20 सूत्री कार्यक्रम पर धक्का लगेगा। आप ही बतलाइये? इसलिये मैं कहता हूं कि आप संविधान में संशोधन लाये, घबड़ाइये नहीं कि इस संशोधन को करने से सरकार बाध्य हो जायेगी। आप यह न सोचें। करैप्शन के लिये कानून बना हुआ है। दो बार अंतुले पर आरोप लगे तो क्या आपने नेशनल सेक्युरिटी ऐक्ट में उसको पकड़ा? उसके खिलाफ आपने कोई दूसरी कार्यवाही की। करैप्शन का वह रिंग लीडर बना हुआ है आपने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की? लेकिन एक प्रावधान है कि करैप्शन करने वाले के खिलाफ कानून है। यह एक बहुत बड़ा काम होता है समाज को चलाने में, समाज को सुधारने में। इसलिये राइट टु वर्क के लिये संविधान में संशोधन की जो मांग है उसको मान लिया जाय। अगर आप इसको मान लेते हैं और इस तरह का संशोधन संविधान में होता है तो इससे आप पर आंच नहीं आयेगी। देश में पूरे लोगों को इम्पलाईमेन्ट मिले, राइट टु वर्क जनतंत्र का एक रूप है, यह सब बातें इसमें रहेंगी। इसलिये इसमें आपको टची होने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा इम्पलाईमेन्ट न हो सकेगा तो थोड़ा तो होगा। जो मेन धारा है, संविधान है उसमें अगर यह संशोधन हो जाता है, देश के हर नौजवान के लिये ऐसा हो जाता है तो उसको अवसर मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता महाराष्ट्र में है ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATPAL MITTAL): You have already taken one hour. Please conclude now.

श्री शिव चन्द्र झा: बेरोजगारी भत्ता महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, बंगाल में है और एक राज्य और भी है जहां अभी भी कानून है गारन्टी देने का। यह आपके राज्यों में है। इसी तरह की यह गारंटी पूरे देश में हो सकती है। इन शब्दों के साथ मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस संशोधन को कबूल कर लें, सारा देश आपके साथ है। यदि आप यह चाहते हैं कि समाजवाद के रास्ते पर देश को चलायें तो इसको स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पेश करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस पर बहस हो, इस पर चर्चा हो और उसके बाद इसको मान लिया जाय।

The question was proposed.

SHRI KALYAN ROY (West Bengal); Sir, i$_n$ the House, we should have some etiquette and decent norms. Mr. Kalp Nath Rai is all along putting his leg on the seat.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KALP NATH RAI): No, no.

SHRI KALYAN ROY; It is not desirable nor proper. A_s Deputy Minister, he should know.

SHRI KALP NATH RAI: You are making a baseless charge. It is not correct,

THE VICE-CHAIRMAN (SHB* SAT PAUL MITTAL): Now, I will call upon Mr. Surendra Mohan to speak.

SHRI SURENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate my colleague, Mr. Shiva Chandra Jha, for having moved this Private Member's Bill.

I would like to recall, Sir, that a similar motion had been moved by Shri Jamuna Prasad Shastri in the Lok Sabha in 1978, and I am happy to say that he also, like Mr. Shiva Chandra Jha, has been a fellow socialist. I, in fact, believe that all those socialists, to whichever party they might belong—now they are scattered in a number of parties, and Mr. Vice-Chairman, Sir, with your permission, may I recall that you also once belonged to the same stream—and I would suppose that all of us would join together in seeing through to the passage of this motion. When Mr. Jamuna Prasad Shastri moved his Motion, then the Lok Sabha was good enough to accept that it be circulated for eliciting public opinion. As I know, Sir, about five lakh persons from all over the country, including Mizoram and other places, signed in support of the Motion.

I would very earnestly request the Law Minister that he should accept that this motion also should be circulated as tihe motion was circulated last time. I would be very glad if he would acMspt this motion right now but even if he cannot accept it right now, he should accept the suggestion for circulating the motion for eliciting public opinion.

Now, Sir, I would like to take this whole issue from rather a negative point. Everyone says that this country is fraught with social tensions. Without subscribing to any kind of economic determinism, I am of the view that much of our social tension has arisen because of mounting unemployment. Shri Shiva Chandra Jha has pointed out how unemployment has grown. I think only yesterday Shri Kalyan Roy had pointed out that during the last eight months the increase in the live registers of employment exchanges was of the proportion of 29 per cent. Now, this figure is alarming. Between 1951 and 1982 unemployment has grown six or seven times. At the same time, Sir, the allocation in the Five-Year Plans has gone up by 60 times. If the allocation in the Five Year Plans has gone up from Rs. 2,300 crores in the First Five-Year Plan to Rs. 1,60,000 crores in the present Plan, that is the Sixth Plan, the increase is of the order of 60 times, When the allocation goes up by 60 times, the unemployment grows by six times. It is a curious situation that the more money we spent, greater the allocation that we make, the greater unemployment comes about and this situation must cause grave concern to all of us because, while on the one hand, we are going to enlarge our allocation for our planned economy, and I am a supporter of planned economy, on the other hand, we are facing greater unemployment. I would like that this country must have a planned and regulated economy. But, I am afraid, Sir, that greater the allocation, greater will be the unemployment, the greater will be the misery of the people and the greater will be the social tensions which will pose a danger as they have been posing a danger to the social fabric of the country and to the national integration. Whether it was the incidence of Shiva Sena in 1968 or 1969 in Bombay or whether there were clashes in Orissa relating to Mar-

waris and Bengalis, or whether there are problems in Bihar or problems anywhere, I am afraid, Sir, that at least one solution to the problem is that you must provide employment to all people to see that the social fabric of the country is not endangered as it is at present. Shri Shiva Chandra Jha has rightly pointed out that there are certain problems. The problems are about the economic viability, the question of mobilisation of resources when we talk of right to work and yet as he has suggested and as I have pointed out, when the resource mobilisation is of the order that after the last twenty years we have been spending sixty times of what we were spending in 1952, 1 think the resource mobilisation cannot be a problem. The resource mobilisation cannot also be a problem if you decide with some determination that work will have to be provided to everybody. In the Janata Party Plan also, in the Janata Party days, there was Food for Work Programme, there was the Integrated Rural Development Plan and there was the programme for the Maxima sation of Irrigation Potential and, therefore, extension of agricultural plan.

At the same time, Janata Party was keen to see that small industry, medium industry, cottage industry is given a priority without in any way endangering or harming the infrastructure of the economy. I am sorry that some of the plans, the employment-generating plans which the Janata Party started were not probably liked by the power that be. Now there is a good scheme, the rural employment generation scheme of the present Government. The problem is—and that was the problem also with the Janata Party plan—that we do not have the mechanism; we do not have the organisation to see that all such plans pre really carried out. There is corruption; there is laxity; there is collusion between the powers that be in the rural areas and those who want to deny employment opportunities to large number of people so that labour is available to them at very cheap rates. This collusion must be broken; this laxity must be plugged and there must be a will, determination and resolution that we will certainly provide work to everybody. You can think of a corporation at the national level, an employment guarantee corporation at the national level. And while we want that the Statute be amended, while we want that right to work should be included in the fundamental rights, we also want that it should not be only an empty slogan; it should not be an empty resolution. We want that it should be backed up by strong economic measures. When you speak of strong economic measures, the main question will be, what is the productive apparatus of the country; what is the productive mechanism. The economists and sociologists will have to come together to decide how best the right of work, once enshrined in the Constitution, can be realised. I am afraid, that no such debate is being undertaken now. If you think of the mounting un-employment, people may be at variance as to whether there are 3 crores or 4 crores or 2 crores; I do not know; but I am afraid that unemployment continues to rise; unemployment con tinues to rise because everywhere we are going in for automation; everywhere we are wanting to give work not on a permanent basis but on casual basis; everywhere every Ministry of the present Government proposes to see that there is contractual work. They do not want to run their own departments; they want to hand over the work to contractors. And all these things show that at some point the energy of the nation is sapped. It is so because there is mounting unemployment. If you want the nation to be strong, then every person must be employed. On the one hand we talk of equality before law and on the other, we do not observe it. May I ask, what is equality before law when there is a person who is unemployed for one year or for a whole lifetime maybe, and there are people who can guarantee him employment and help to remove him from employment?

[Shri. Surendra Mohan]

How can they be equal before law? We are making a mockery of law, mockery of democracy and mockery of every tenet of civilised society if we allow, millions of people to remain unemployed and unemployment continues to grow. This is a warning, a grave warning not only to the ruling party today but the bell tolls for all of us. I would therefore humbly submit that some steps must be taken, some resolute steps must be taken to see that we provide employment to all.

Thank you.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री शिव चन्द्र झा जी ने जो अपना विधेयक प्रस्तुत किया है, उसकी काफी विस्तारपूर्वक उन्होंने चर्चा की। उन्होंने यह भी सुझाया कि जिन लोगों को रोजगार का अधिकार संविधान में दिया जायेगा, उसके लिये साधन भी कहां से जुटाये जा सकते है। लेकिन इस सबके बावजूद सब कुछ निर्भर होता है इच्छा-शक्ति पर। अगर किसी देश के चलाने वाले लोगों की इच्छा-शक्ति मजबूत हो, उनकी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो फिर रास्ता निकल सकता है, जहां चाह वहां राह। अगर चाह है तो राह भी है और यदि चाह नहीं है तो फिर उसका कोई रास्ता निकल नहीं सकता है। बहुत लम्बे समय से इस पर बहस भी चलती रही है, जुगाड़ भी होता रहा है, लेकिन जान बूझकर इस देश में जो सत्ता पर लोग रहे हैं या शासन चलाने वाले लोग रहे हैं, चाहे वे प्रशासन में हों या राजनीति में हों या और कही हों, इस समस्या का समाधान वे चाहते ही नहीं है। लोगों का इरादा है, सरकार चलाने वाले और शासन चलाने वाले लोगों का इरादा है कि इस देश क अंदर बेकार रहे, भुखमरी रहे, गरीबी रहे, अशिक्षा रहे। एक तरफ जब लोकतंत्र बचाओ का नारा लोग उठाते है और कहते है लोकतंत्र गतिशील हो लेकिन लोकतंत्र के जितने दुश्मन है उन में सबसे बड़ा दुश्मन बेकारी है, अशिक्षा है, भुखमरी है। एक तरफ हिन्दुस्तान में आधे से अधिक लोग भूख की अग्नि में जल कर राख हो रहे हैं दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में 5 प्रतिशत आदमी जो ऊपर के हैं वे भोग की अग्नि में जल कर राख हो रहे हैं, ये लोग इस देश में शासन चला रहे हैं। आधे से अधिक लोग तो भूख की आग में जल रहे हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, थोड़े से लोग, वे भोग की अग्नि में जल रहे हैं। लेकिन जो भोग के चरम शिखर पर बैठे हुए हैं या गरीबी के महासागर में जो कुछ कमल खिले हुए हैं, इन कमलों को कुछ पता ही नहीं लगता की जंगल में धतूरे के फूल का क्या हाल हो रहा है। गरीबी के महासागर में इन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो कुछ कमल निरंतर खिलते रहे हैं उनको बाकी के बारे में पता नहीं। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि खूब ऊंचे पर खड़े आदमी को नीचे कुछ दिखायी नहीं पड़ता और नीचे की चीज उनको अति छोटी दिखायी पड़ती है। जहां बैठ कर सोचते है उन बेकारों के बारे में और भूखों के बारे में, तब लगता है जो गरम गरम पुलाव, मुर्ग मुसल्लम खाने वाले लोग हैं, टोस्ट बटर खाने वाले लोग है, उनको यह महसूस होता है कि ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम सूखी रोटी जरूर मिलती है। वह यह नहीं सोचते कि भूखे भी लोग सो जाते हैं। जहां तक बेकारी का सवाल है, मेरा आरोप है कि हिन्दुस्तान के पांच दस लोग शासन सत्ता को चलाने वाले लोग है उनके घरों में बेकारी का कोई चिन्ह नहीं दिखायी देता और यदि बेकारी हो भी तो उनके रोटी रोजी चलाने के कई साधन हैं। बाकी तो हिन्दुस्तान में बसने वाले गरीब हैं, पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासी गिरिजन, जंगलों और पहाड़ियों में लकड़ी काटने वाले लोग हैं,

उनके यहां जो अभाव है, दरिद्रता है उसके बारें में वह अंदाजा नहीं करते। बेकारी के दफ्तर में जो रजिस्टर है उसमें जो बेकार लोगों का नाम रखा जाता है उस में लिखा जाता है शिक्षित बेरोजगार, जिसने बी ए की डिग्री एम ए की डिग्री ले लिया या मैट्रिक पास कर लिया। जब उन को भूख लगती है तो शायद उनको भूख सताती है एक किलो की ओर अशिक्षित लोगों को भूख सताती है 100 ग्राम से। भूख में कोई अंतर नहीं होता है चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, शहर में बसने वाले लोग हों या गांव में बसने वाले लोग हों। भूख की अग्नि दोनों को जलाया करती है। तो शिक्षित लोगों का कहीं कहीं रजिस्टर में नाम लिख देते हैं और बताया जाता है कि इतने बेरोजगार है। लेकिन बाकी जो लोग है गांव के रहने वाले, जंगल में रहने वाले, हल जोतने वाले, कुदाल चलाने वाले, जूते पर पालिश करने वाले, वगैरह वगैरह ऐसे लोग जो देहातों में है उनका आज तक हिन्दुस्तान में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया और न हो सर्वेक्षण हो सकता कि कितने असली मानों में बेकार है, चाहे पूर्ण बेकार हों, अर्ध बेकार हो, किसी तरह से बेकार हों। गांव के अंदर जो चार छः महीने काम करते है, बाकी दिनों बेकार रहते है, वह बेकार कितने निकल आयेंगे। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाये, तो हिन्दुस्तान में 70 करोड़ आदमी हैं और अगर पांच आदमियों का एक परिवार माना जाये, तो 14 करोड़ परिवार होता है। हर परिवार में अगर एक बेकार हो तो मोटा मोटा हिसाब लगाया जाये तो 14 करोड़ आदमी इस देश में बेकार है। एक तरफ हिन्दुस्तान में इतना मानव समुदाय बेकार बैठा हुआ है दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में ऐसी योजनायें चलाई जाती हैं, ऐसी मशीनरी बैठाई जाती है जिसके चलते हजारों हजार आदमी बेकार हो जायेंगे। अभी टाटा के आधुनिकीकरण के नाम पर भारत सरकार की ओर से पैसे दिये जा रहे हैं। अगर यह मशीन लगा दी जाये जिस को कम्प्यूटर कहते हैं तो टाटा में पांच छः हजार मजदूर बेकार होने वाले हैं। एक तरफ बेकारों को रोजगार देने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मशीने बैठा कर काम करनें वालों के हाथों से काम छीनो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब गाड़ी उलटी दिशा में चल पड़ी है तो उस गाड़ी की दुर्घटना कहां होगी और कौन मरेगा इस का कोई ठिकाना नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था की जो दृष्टि है वह उल्टी गाड़ी पर चल रही है और उस की पटरी की दिशा अलग है। चाहे समाजवाद का नारा दे दीजिये– अगर समाजवाद का नारा लगाने से समाजवाद आता तो कब का आ गया होता। हर दीपावली को हिन्दू परिवार में पलीता लगा कर कहते है गरीबी भागे, अमीरी आवे, लेकिन पलीता लेकर कहने से न गरीबी भाग रही है, न अमीरी आ रही है।

[उपसभाध्यक्ष (डा० श्रीमती नाजमा हेपतुल्ला) पीठासीन हुई]

इच्छा-शक्ति और संकल्प शक्ति से आप देश को किसी दिशा में ले जा सकते है। बेकारी मिटनी चाहिये, भुखमरी मिटनी चाहिये, बेरोजगारों को काम देना चाहिये अगर इस के बारे में संकल्प शक्ति है और इच्छा मजबूत है तो कर सकते है। सत्ताधारी पक्ष की ओर से कहा जायेगा कि इतने बेरोजगारों को काम देने के लिये पैसा कहां से लायेंगे। मैं कहूंगा कि पैसा लाने के लिये हम को और आपको हिसाब लगा कर देखना है। सीधी बात है। कल्पनाथ राय जी बैठे हैं, और भी कई साथी है। हम लोग नारा लगा कर जेल जाते थे,

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

हमारा नारा होता था, 'गांधी लोहिया का सन्देश, एक व्यक्ति एक पेशा, खेती, नौकरी और व्यापार, एक आदमी एक रोजगार' है आप में हिम्मत? एक पेशा रहे, खेती करे या नौकरी करे या व्यापार करे। हिन्दुस्तान के अन्दर बड़ी बड़ी कम्पनियों का मालिक बनता है, उसी का बेटा, नाती, पोता, भाई, भतीजा, कलक्टर, कमिश्नर, एस डी ओ पुलिस कप्तान सब बन जाता है। एक परिवार है जिस में आई ए एस बाप से लेकर बेटा तक सब होते चले जाते है। हिन्दुस्तान में कुछ परिवार ऐसे है, जो आई ए एस पैदा करने की फैक्ट्री बने हुए हैं। उन को क्या पता लगे। उन के यहां आई ए एस पैदा होता है, बाकी लोगों के यहां किरानी और चपरासी पैदा होने की भी काबलियत नहीं होती। आप हिसाब लगा कर देखें। मैं ने कहा खेती, नौकरी और व्यापार, एक आदमी एक रोजगार एक आदमी एक पेशा रहेगा। अगर व्यापार करता है तो व्यापार करेगा। जो व्यापार में रहेगा, उस की सारी खेती छीन लीजिये और जिन के हाथ में काम नहीं है उन को वह जमीन दे दीजिये। जिसके पास जमीन रहेगी उन को नौकरी मत दीजिये। सरकारी नौकरी उस को मिलेगी जो भूमिहीन होगा, सरकारी नौकरी उस को मिलेगी जिसके परिवार में एक आदमी किसी रोजगार में नहीं होगा। आरक्षण के मामले को लेकर हिन्दुस्तान के बड़े लोगों के पेट में चूहा कूदता है, हमें वह आरक्षण नहीं चाहिये। आप यह कर दीजिये कि जिस परिवार में एक भी आदमी को रोजगार नहीं है सरकारी काम पहले उस को दिया जायेगा। हम को आरक्षण नहीं चाहिये यही बात कर दो। आप क्यों नहीं सरकारी नौकरी का कोटा बनाते। गेहूं का कोटा, कपड़े का कोटा, तेल का कोटा, उसी तरह सरकारी नौकरी और रोजगार का भी कोटा रहेगा। कोटे का मतलब है कि उस आदमी को आप पहले रोजगार देंगे जिस परिवार में एक भी आदमी रोजगार नहीं पाया हुआ है। हम आप को सुझाव देते हैं कि एक कानून यह बनाइये और यह कर दीजिये कि एक आदमी एक रोजगार चलायेगा, तब जितना काम बचेगा वह बाकी लोगों को दिया जा सकता है।

दूसरे शिव चन्द्र झा ने कहा कि आमदनी पर प्रतिबन्ध लगाइये। मैं कहता हूं कि आय पर प्रतिबंध लगाने से ज्यादा जरूरी है कि आप खर्चे पर प्रतिबंध लगाइये। बड़ी बड़ी कम्पनियां है। आप कम्पनी एफेयर्स के मालिक है। टाटा और बिड़ला के बेलैंस शीट को निकाल कर देखिये। पत्नी जायेगी इलाज पर तो कम्पनी में खर्च, तीर्थ करने कैलाश जायेगी तो कम्पनी में खर्चा, बद्रीनाथ जायेंगे तो कम्पनी में खर्चा, बेटा पढ़ रहा है तो कम्पनी में खर्चा, इलाज हो रहा है तो कम्पनी में खर्चा। जितने खर्चे है वे सारे कम्पनी में दर्ज कर दिये जाते है क्योंकि खर्चे पर एक निश्चित सीमा तक आप कर में छूट देते हैं। तो आयकर बचाने के लिए ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हिन्दुस्तान के हैं, सारे नाजायज खर्चे अपनी कंपनी के खातों में दर्ज करते हैं, अपने परिवार पर खर्च करते हैं और नाजायज तौर पर इससे भी ज्यादा खर्चा करके आयकर बचाते हैं। तो आप यह निश्चित करिये कि इस सीमा से अधिक खर्चा जो भी करेगा उस पर सख्ती के साथ कर वसूल करेंगे। जो आदमी खर्चा कम करके रुपया बचाता है, उस पर तो आप टैक्स लगाते हैं, लेकिन जो शराब पीने में पैसा फूंक दे, पंचसितारा होटलों में रहे, एयर कंडीशन बंगलों में रहे तो उस पर सरकार इनकम टैक्स नहीं लगाती है। कैसा उल्टा हिसाब है कि पसे की बचत करे उस पर सरकार इनकम टैक्स ले ले, बचने वाले मारे जाते हैं और लुटाने वाले मौज उड़ायें। तो आप एक सीमा से ज्यादा किसी भी

व्यक्ति को खर्चा न करने दें । अगर उससे ज्यादा खर्चा वह करता है तो उसको अपराधी मानें । आपकी ये राष्ट्रीय बचत स्कीमें तभी सफल हो सकती हैं जब आप इस महाराक्षस का, भोग के महाराक्षस का बध करेंगे । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हिन्दुस्तान की अर्थ नीति सुधर नहीं सकती है । इसीलिए मैंने कहा कि आप विलासिता के सामान पर रोक लगायें । हिन्दुस्तान का अगर कहीं कुछ बनेगा तो तभी बन सकता है ।

श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बाजार में गया तो मैंने एक शीशी में "सैक्स अपीलिंग परफ्यूम" देखा । वाह रे हिन्दुस्तान, यहां रोटी नहीं मिल रही है, यहां पर सैक्स अपीलिंग परफ्यूम बिक रहा है । बेरोजगारों को रोजगार भी देंगे, सैक्स अपीलिंग परफ्यूम भी बेचेंगे । यह दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते ।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र): आपको देखकर वह सैक्स अपील का क्या करेंगे ?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : वह इसमें इजाफ़ा नहीं कर सकते लेकिन श्रीमन्, दस हजार वर्ष तपस्या करने के बाद विश्वामित्र भी... (व्यवधान)

SHRI ARVIND GANESH **KULKARNI:** This sex-appealing perfume is only *lor* youngsters and not people like you and me.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं नौजवानों के लिए रोटी की बात कर रहा हूं । आप रोटी दोनों वक्त उनको दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, सोने के लिए बढ़िया बिस्तर दे दीजिए तो सैक्स अपीलिंग परफ्यूम की आवश्यकता उसके बाद ही पड़ेगी । भूखे इंसान के लिए सैक्स अपीलिंग परफ्यूम बेकार की चीज है । जितना बिलासिता का उत्पादन देश में हो रहा है उन सारे उत्पादनों को आप बन्द कीजिए तब हिन्दुस्तान तरक्की करेगा । जब तक तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दे देते तब तक उससे ज्यादा कीमत का उत्पादन आप नहीं करेंगे ।

श्रीमन्, आपने नाम सुना होगा कि हिन्दुस्तान के कितने ही लोग माउत्से तुंग को अपना नेता मानकर जैल में बन्द हुए थे । ऐसा क्यों हुआ ? ऐसा उनके विचारों के कारण, आदर्शों के कारण हुआ । पंडित जवाहरलाल नेहरु को महात्मा गांधी ने, बड़े बाप के बेटों को, गरीबी की जिन्दगी बिताने के लिए तैयार कर दिया । यह सबसे बड़ी सफलता थी जिसने अपनी ताकत से बड़े-बड़े लोगों को महलों से निकाल कर गरीबी की जिन्दगी बिताने पर मजबूर किया था । आपके पास क्या आदर्श हैं ? आपके पास पाउडर, क्रीम व इत्र है । हिन्दुस्तान के गरीबों को आप उपदेश देते हैं, हिन्दुस्तान के लोगों को आदर्श का उपदेश देते हैं जिससे हमारा देश और निर्धन हो रहा है । हमारा देश गरीबी की स्थिति में हैं और उनको आप उपदेश देने चले हैं—पर उपदेश कुशल बहुतेरे पहले आप अपने आचरण को सुधारो, नहीं तो याद रखिये आपके अन्दर से जो

[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

सुगन्धित पर्फ्यूम की सुगन्धित हवा निकल रही है, किसी दिन उसी शरीर से जलती हुई लाश की बदबू निकलेगी । इसलिए समय रहते हमको सावधान हो जाना चाहिए । इसलिए मनुष्य मात्र को हिन्दुस्तान में ज्यादा दिन तक जिन्दा रखना है तो भोग के रास्ते को छोड़कर उत्पादन व बचत के रास्ते पर चलना होगा । इसलिए मैंने कहा कि विलासिता के उत्पादन पर रोक लगाइये । आइये मानवीय श्रम पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दें । महात्मा गांधी ने कहा था मानव श्रम की आवश्यकता होगी और श्रम-मूलक उत्पादन को जोड़ना होगा । ये सारी बातें अर्थ शास्त्रियों की हैं, मैं अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं गांव का साधारण किसान हूं लेकिन थोड़ा सा हाई स्कूल और कालिज में अर्थशास्त्र पढ़ा था । उत्पादन के लिये लैंड, लेबर, कैपिटल और आर्गेनाइज चाहिये । उत्पादन के लिये ये चार चीजें जरूरी हैं । इनमें कौन सी ज्यादा है ? जमीन कम है, पूंजी कम है, संगठन कम है । हमारे पास अगर किसी चीज की बहुलता है, तो वह है मानव श्रम । मानव श्रम की बहुलता है । हमारे घरों का नियम है कि जो चीज घर में ज्यादा हो उसको ज्यादा खर्च करो और जो चीज घर में कम हो, उसमें कटौती करो । पूंजी कम है, जमीन कम है । केवल मानव श्रम ज्यादा है । हमारे उत्पादन का आधार होना चाहिये पूंजी में कमी, जमीन में कमी और मानव के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की योजना बने । हजारों लोग, लाखों लोग काम करने लगेंगे । लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या है ? जमीन कम, पूंजी ज्यादा और मानव श्रम कम । पैसा लाओगे कहां से ? इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड से लाओ । "यावत जीवेत् सुखम् जीवेत्, ऋण कृत्वा घृतम् पिवेत्" । जब तक जीओ, सुख से जीओ, ऋण लेकर घी पी लो । लेकिन आज कर्जा लेकर पानी नहीं पीयेंगे बल्कि व्हीस्की पियेंगे ।

मानव श्रम गांधी जी का दर्शन था । यह हम लोगों का दर्शन नहीं है । देश ने गांधीवाद का रास्ता अपनाया । गांधी का नाम लेने वाले गांधी के विचारों की हत्या कर रहे हैं । नाथू राम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी और गांधी जी का नाम लेने वालों आप गोडसे से ज्यादा हत्यारे हैं । आपने गांधी जी के विचारों की हत्या की है । इस देश में गांधी जी के विचारों को मारा है । गांधी जी की मूर्ति की पूजा करो, उनके विचारों को मारने का काम करो । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मानव श्रम पर आधारित रहो । गांधी जी ने कहा था कि चर्खे का इस्तेमाल करो । चर्खा कोई लकड़ी का खिलौना नहीं है । गांधी जी का वह चर्खा एक दर्शन था । उससे गरीब लोगों को, कुटिया में बसने वाले लोगों को, साधारण लोगों को रोटी,

रोजगार मिलेगा । नौजवान को पहले चाहिये रोटी तब चाहिये कपड़ा । एक कारखाने में एक मजदूर मफतलाल के कारखाने में, अरविन्द मिल में, कानपुर की मिल में, टाटा कपड़ा मिल, बिरला क्लाथ मिल में जितना कपड़ा तैयार करता है उतना कपड़ा अगर गांव के गरीब जुलाहों को तैयार करने के लिये दिया जाये तो 12 मजदूरों को रोजगार मिलेगा । जब से देश आजाद हुआ है हिन्दुस्तान के कुटीर उद्योग मरते जा रहे हैं। मधुबनी, दरभंगा का मैं रहने वाला हूं । एक समय था जब मधुबनी का खादी नामी था और हजारों जुलाहा मुसलमान काम में लगे थे । उसके घर में खटपट-खटपट चलती रहती थी । हमारे बच्चे उनके साथ खेलते रहते थे । वहां हाथ से बुने कपड़े तयार होते थे लेकिन इन मिलों के आने से टेरालीन, टेरीकाट और दूसरे कपड़ों के आने से उनका काम बन्द सा हो गया। आपने गांधी जी के विचारों को मार कर हजारों गरीबों, जुलाहों को निकम्मा किया है । बम्बई और कलकत्ता के फुटपाथों पर वे भूखे मर रहे हैं । जो उत्पादन हाथ से होगा उसमें छोटी मशीन का और जो छोटी मशीन से हो सकता है उसमें बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा । मेरा कहना है कि हाथ और मशीन की प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिये । अर्थशास्त्र का साधारण सा सिद्धांत है अगर हाथ और मशीन में टकराव होगा तो हाथ हारेगा और मशीन जीतेगी । आपका काम होना चाहिये। हाथ और मशीन की स्पर्धा को बंद करिये । दोनों में कम्पीटीशन नहीं होना चाहिये । मानव श्रम को खत्म करिये । बड़े-बड़े पूंजीपति लोग पैसा लगाकर साबुन तैयार कर सकते हैं तो गांव के नौजवान गरीब लोगों को साबुन बनाकर बेचने का रोजगार क्यों नहीं दे सकते । वे हजार, दो हजार रुपया लगा कर साबुन बना सकते हैं, कपड़ा तैयार कर सकते हैं । टाटा साबुन बनाये, कपड़ा बनाये, कोकोनट आयल बनाये, हवाई जहाज वह बनाये, रेल गाड़ी वह बनाये। टाटा तो ऐसा हो गया कि जैसे वह भगवान के घर से बनकर आया हो कि जाओ टाटा महाराज जो चाहो बनाओ। क्या बाकी लोगों को, देश के और लोगों को कुछ भी बनाने का अधिकार नहीं है। विमको माचिस माचिस बनाने का काम करता है। माचिस बनाने का काम गांव के लोगों को, गरीब लोगों को मिलना चाहिये। चौधरी चरण सिंह जब सत्ता में थे तो उन्होंने अर्थ मंत्री होने की हैसियत से विमको माचिस पर ज्यादा टेक्स लगा दिया था और जो हाथ से दियासलाई बनाई जाती थी उस पर टेक्स कम कर दिया था। इससे दक्षिण भारत के 20–25 हजार लोगों को सलाई बनाने का काम मिल गया था । कारखानों को घाटा होने लगा था । लेकिन आपने फिर कारखानों में बनने वाली माचिसों पर छूट दे दी, विमको पर छूट दे दी और इससे 20–25 हजार लोगों के हाथ से आपने रोजगार छीन लिया । विमको सलाई सस्ती होने लगी और हाथ की बनी सलाई मंहगी हो गई तो उनका

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

रोजगार बन्द होने लगा । इसी तरह से जूते बनाने के कारखानों के बारे में है। देश के हजारों लोग हमारे मोची भाई, चमार का काम करने वाले गांव में जूते बनाते हैं। उनके हाथ के बने हुये जूते बाटा का सोल लग कर बाजार में बेचे जाते हैं । बाटा का जूता आपने गांव-गांव में पहुंचा दिया है और हजारों मोची भाईयों को बेरोजगार कर दिया है । उनके हाथ की रोटी छीन ली गई है । पहले हजारों गांवों में तेली भाई सरसों का तेल निकाला करते थे, वे भी अब बेकार हो गये हैं । आपने अब पहलवान छाप, हाथी छाप, और घोड़ा छाप, न जाने क्या चीजें निकाल दी हैं । गांवों में कोल्हू बन्द हो गए हैं । गांवों के अन्दर जो गरीब लोग थे, उनके हाथों की रोजी छीन ली गई है । बेरोजगारों के लिये हम एक छोटा सा संशोधन संविधान में करना चाहते हैं । आप हमें रोजी का हक दे दीजिये । जिन लोगों की रोजी छीन ली गई है, जिन मोचियों की रोजी-रोटी छीन ली गई है, जिन कुम्हारों की रोजी-रोटी छीन ली गई है, जिनके कुटीर उद्योग छीन लिये गये हैं, उनके लिये हम यह छोटा सा संशोधन चाहते हैं । आप बड़े-बड़े घरानों को बढ़ाते जा रहे हैं । आपको इन घरानों पर प्रतिबन्ध लगाना होगा और गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार देना होगा। चलो गांव की ओर, यह आपका नारा होना चाहिये । आप गांवों का औद्योगीकरण कीजिये । छोटे-छोटे उद्योग गांवों में खोलिये । दूसरे शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उद्योगों का ग्रामीण-करण कीजिये । जो उद्योग हैं उनकी पूंजी में ही गांवों में उद्योग खोलिये । अगर आप ऐसा करेंगे तो हिन्दुस्तान के हजारों नवजवानों को रोजगार मिलेगा। आज हालत यह है कि गांव का नवजवान बी० ए० या एम० ए० पास करने दिल्ली युनिवर्सिटी में या मिथिला युनिवर्सिटी में जाता है तो वह सूट-बूट, कोट-पेन्ट, टाई-टोप में रहता है और सिनेमा देखता है, बढ़िया मकान में रहता है और उसके जूते चमचमाते रहते हैं । जब वह पढ़ाई खत्म करके गांव में जाता है, तो उसकी वही झोंपड़ी मिलती है, जिसमें उसकी पत्नी रहती है जिसके शरीर से मिट्टी और पसीने की बदबू आती है । शहर में वह उन लड़कियों के बीच में रहता है जिनसे सेन्ट की सुगन्ध आती है । यह आप क्या शिक्षा दे रहे हो ? आप यह यूरोप की शिक्षा दे रहे हो, लन्दन और बर्लिन की शिक्षा दे रहे हो, न्यूयार्क की शिक्षा दे रहे हो । यही वजह है कि उसके हाथ में राइफल आती है, तो उससे प्रहार करता है और अगर उसके हाथ में एटम बम दे दिया जाये तो वह इस देश को भी ध्वस्त करने के लिये तैयार हो जायेगा । एक तरफ तो कुछ लोग मौज उड़ाते हैं और दूसरी तरफ लोगों को रोजी-रोटी नहीं मिलती है। इसलिये आप इस नीति को छोड़ो ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैंने कहा कि आप जीवनोपयोगी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाइये । जीवनोपयोगी वस्तुएं बाहर से मत मंगाइये । देश में ही बनाइये । मल्टी नेशनल्स के जरिये से आप बाहर से माल मंगाते हैं । आप इन चीजों को देश में ही बनाइये । अगर आप इन चीजों को देश में बनायेंगे तो हमारी कुशलता बढ़ेगी और हाथ में सफाई आयेगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आप में कल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है और अगर आप में देश को ऊंचा बनाने का सपना है तो आप गांवों की तरफ ध्यान दीजिये। लेकिन हमने तो एक गाना सुना है:—

दो तरह के नेता होते हैं,
एक देश की खातिर मरते हैं,
एक देश को खाकर मरते हैं ।

आज तो देश को खाकर मरने वालों की संख्या अधिक है । आप सावधान हो जाइए । लोगों को रोजी-रोटी का अधिकार दे दीजिये । हमने संविधान में बहुत से अधिकार दे रखे हैं । यह एक मामूली-सा अधिकार है, आप हमारे देश के बच्चों को रोजी-रोटी का हक दे दीजिए । सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों को रोजी-रोटी दे । हमारे देश के गरीब लोग रोजी-रोटी मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगते हैं। उनकी मांग है —

छोटी दो, या मोटी दो, इंदिरा देवी रोटी दो, इंदिरा देवी रोटी दो ।

श्री नन्द किशोर भट्ट (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, काफी दिलचस्पी से मैं अपने पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था । खासकर श्री शिव चन्द्र झा ने जो प्रस्ताव रखा है मैंने उस पर उनके विचार भी ध्यानपूर्वक सुने । इस बात पर हम सभी सहमत हैं कि इस देश में समाजवाद आये और समाजवाद के लिए जो भी हम लोगों को कार्य करना चाहिये, जो भी महात्मा गांधी और जवाहरलाल जी ने हमारे सामने उसकी रूपरेखा रखी उसके अनुरूप हमको चलना चाहिये । इस बारे में हमारी पार्टी की कभी भी कोई दो राय नहीं रही । पंडित शिव चन्द्र झा जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पंचवर्षीय योजना की भूमिका की ओर भी हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में योजनाबद्ध रूप से मिक्स्ड एकानामी, मिली-जुली अर्थ व्यवस्था को स्वीकार किया गया है । मिली-जुली अर्थ व्यवस्था में पब्लिक सैक्टर के बारे में यह कहा गया था कि सारे उद्योगों की हमारे देश के अर्थ-तंत्र में बहुत उच्च व्यवस्था रहेगी । पिछले तीस सालों में, जब से कांग्रेस सत्ता में आई है हमने योजनाबद्ध तरीके से देश के विकास का काम चलाया है । आज सार्वजनिक उद्योग, पब्लिक सेक्टर हमारे देश में बहुत बड़ा स्थान रखता है । मगर यह बड़े अफसोस की बात है कि वे लोग जो सार्वजनिक उद्योगों की बात करते हैं और प्रकट करते हैं कि देश में समाजवाद आये वही लोग सार्वजनिक उद्योग को

[श्री नन्द किशोर भट्ट]

कमजोर करने के लिए पूंजीवादियों का साथ देकर काम करते हैं । जो इस प्रकार के लोग हैं वे इन लोगों के साथ मिलकर पब्लिक सेक्टर को नुकसान पहुंचाते हैं । बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके बाद यह आशा कि जाती थी हम इसके द्वारा अपने देश की अर्थ-व्यवस्था को लाभ पहुंचायेंगे, मजबूत बनायेंगे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण से निश्चित रूप से बहुत हद तक हम आगे बढ़े हैं । जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनको जैसे कि कोई रिक्शा वाला है उसको रिक्शा के लिए कर्जा बैंकों से मिल सकता है, उनको यह मिल रहा है । साधारण आदमी को दुकान लगाने के लिए पूंजी आज बैंकों से मिल सकती है । इसी प्रकार से कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया । बहुत से हमारे बड़े-बड़े उद्योग हैं जो कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं । तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे देश में आज जितने भी हमारे बड़े-बड़े कारखाने हैं वे पब्लिक सेक्टर में हैं और इस क्षेत्र का देश में बहुत विकास हुआ है । हमारी मंशा इससे और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि छठी पंचवर्षीय योजना में पब्लिक सेक्टर के लिये 97.5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है । अभी हमारे एक साथी ने जो केवल "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" हुक्मदेव नारायण यादव जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति ऐसी जो बात की वह नहीं करनी चाहिए । मोटे तौर पर एक साधारण कार्यकर्त्ता होने और इस देश का नागरिक होने के नाते मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि-सार्वजनिक उद्योग जिनका देश की अर्थ व्यवस्था में अपना विशेष स्थान है, इसमें हमने कुल मिलकर किस हद तक सफलता पाई है । यह सब को विदित है कि उन उद्योगों को पीठ पर छुरा भोंकने की वे बात कर रहे हैं । कितने ही उद्योग ऐसे हैं जहां हमारे इन्हीं साथियों ने, हमारे इन भाईयों ने मिलकर इस बात की कोशिश की कि हम पब्लिक सेक्टर को इन-एफिसियेन्ट बनायें । पब्लिक सेक्टर का काम ज्यादा हो, पब्लिक सेक्टर में उत्पादन बढ़े । पब्लिक सेक्टर एफिसियेन्ट बने, उनकी तरफ से इसकी कोई विशेष कोशिश नहीं की जा रही है । प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे सामने नारा दिया 'श्रममेव जयते" श्रम को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने का उन्होंने धीरे-धीरे प्रयत्न किया और कांग्रेस पार्टी इसको पूरा करने की कोशिश कर रही है । उन्होंने कहा कि देश की गरीबों केवल नारों से नहीं जायेगी बल्कि देश की दौलत को बढ़ाने से जायेगी । सब कहते हैं कि दौलत को बांटना चाहिए । लेकिन इसके लिये पहले दौलत पैदा करनी होगी, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा, उत्पादन को बढ़ाना होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन सी पार्टियां हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम के लिये आगे

आकर कहती हैं कि आइये हम लोग मिल-जुलकर काम करें ? नकारात्मक राजनीति से देश का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी हमारे भाई हुक्मदेव नारायण यादव ने 20-सूत्री कार्यक्रम का मजाक उड़ाया । क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि उसमें गरीबों के लिए, सर्व-साधारण के लिए, मजदूरों के लिए देश को उन्नत करने के लिए जो योजनाएं रखी गई हैं, आप बड़ी-बड़ी पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं, उन बड़े बड़े पोस्टरों की बात करते हैं उनको आप समझ सकते हैं, कालेज के विद्यार्थी समझ सकते हैं, आचार्य समझ सकते हैं, विद्वान समझ सकते हैं मगर सड़क पर काम करने वाले मामूली हमारे साधारण मजदूर भाई हैं उन्ह इससे कोई तात्पर्य नहीं उसके सामने तो सूत्र होना चाहिये कि क्या काम करना है। आपने किस हद तक किया उसके लिए काम करने की कोशिश की। आज सारे देश में बीस सूत्री कार्यक्रम चल रहा है और प्रगति हो रही है। कई जगहों में मैं जानता हूं मैंने देखा है कि विरोध पक्ष में लोग संकीर्ण भावना से कार्य करते हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी कोई अच्छा कार्य देश में करने की कोशिश करती है, प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जब किसी काम को आगे ले जाना चाहती है तो उसको कमजोर करना शायद हमारे विरोध पक्ष का एकमात्र लक्ष्य रह गया है । राईट टू वर्क की बात की जाती है, काम करने के अधिकार की बात की जाती है मगर इसके साथ-साथ कुछ कर्त्तव्य भी होते हैं। अधिकार और कर्त्तव्य बराबर साथ-साथ चलते हैं। संसार में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिसकी दुहाई दी जाती है वह बगैर अनुशासन के, बगैर काम किये, बगैर दौलत के बढ़ाए आगे बढ़ा हो । मगर वहां की ट्रेड यूनियन की, वहां की अर्थ-व्यवस्था की तारीफ करेंगे। चीन में जाएंगे तो वहां की अर्थ-व्यवस्था की तारीफ करेंगे। जहां भी जाएंगे वहां की तारीफ करेंगे मगर हमारे देश में आज जो हमारी अर्थ-व्यवस्था है उसी को कमजोर करने के लिए हमारे सभी लोग मिल कर एक हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन गिरे। मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं। बम्बई की कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल को ही ले लीजिये। उस हड़ताल के पीछे क्या कोई विचार है, क्या कोई दर्शन है, क्या कोई चार्टर आफ डिमांड है? सिर्फ एक गैर जिम्मेदार आदमी ने कह दिया कि मजदूरों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये। कौन कहता है कि नहीं बढ़नी चाहिये, मजदूरों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये, गरीबों का रहन-सहन का दर्जा ऊपर उठना चाहिये । मगर क्या यह नारों से ऊपर उठ जाएगा। आज जिन लोगों ने बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल करवाई है क्या वे इस बात से इन्कार करते हैं कि इस हड़ताल में मजदूरों का 60 करोड़ रुपये का नुक्सान वेतन में ही चला गया। यह जो नुकसान

[श्री नन्द किशोर भट्ट]

उनको हुआ है शायद इस जन्म में कमी पूरा नहीं हो सकेगा। मैं पुनः जन्म में विश्वास नहीं करता हूं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, झा जी का विचार अच्छा है, बड़ा अच्छा है, परन्तु वे यह भी विचार करें कि केवल नारे लगाने से मोटी मोटी बातें करने से, कहने से कभी देश तरक्की नहीं कर सकता है। आज आप रूस की बात करते हैं मगर यह भूल जाते हैं कि रूस जैसा अनुशासन, पीठ के पीछे बन्दूक की नाल होती है और उसके आगे काम करने का तकाजा है और उसी के द्वारा, काम करने के द्वारा रूस ने तरक्की की है और आज वहां जो कुछ भी हुआ है वह सब अनुशासन के बल पर ही हुआ है। लोगों ने मेहनत की है और उसके बल पर सब कुछ हुआ है। जापान की बात करते हैं। जापान में मजदूर वहां हड़ताल नहीं करते हैं, आपसी मतभेदों को बैठ कर दूर करते हैं परन्तु हम वहां जाकर जापान की तारीफ करते हैं मगर हमारे देश में आकर सब उच्छी बातों को जो दूसरे देशों में देखते हैं उनको भूल जाते हैं और बराबर इस कोशिश में रहते हैं, कि वर्ग का संघर्ष बराबर चलता रहे। आज जमाना वर्ग संघर्ष का नहीं है, वर्ग सहयोग का है। आप जानते हैं कि स्कैंडेनेवियन कंट्रीज में सहाकारिता आन्दोलन सक्सेसफुल हो गया। वहां पर यह आन्दोलन कैसे चला। जनता को खाने के लिए चीजें नहीं मिलती थीं। कुछ पूंजीपतियों ने इतने दाम बढ़ा दिये कि लोगों के लिए उन चीजों को खरीदना सम्भव नहीं था। उन लोगों ने प्रण किया कि हम दुकानों से कोई सामान नहीं लेंगे। उन्होंने मिल कर सह/सहकारिता के आधार पर अपने गहने बेच कर, जेवर बेच दिये, पूंजी घर से निकाल कर दी, उसका परिणाम यह हुआ कि उन देशों में हर चार में से तीन आदमी कोआप्रेटिव मूवमेंट के सदस्य होते हैं और सब मिलजुल कर के सहकारिता के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली है कि जो निजी उद्योग के लोग हैं, निजी दुकानदार हैं जिनको आप कैपिटलिस्ट कह सकते हैं, छोटे-छोटे दुकानदार कह सकते हैं। आज उनकी हिम्मत नहीं होती है कि चीजों के दाम बढ़ा दें। मगर आज हमने अपने यहां सहकारिता को आगे बढ़ने का, पूंजी बढ़ाने का लाभ का साधन मान कर सहकारिता का उपयोग करना चाहते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में यह आन्दोलन आगे नही बढ़ पाया है। यही कारण है कि जहां ट्रेड यूनियन मूवमेंट को जहां मजदूरों को काम करने के लिए तत्पर करना चाहिये, तैयार करना चाहिये, मेहनत करनी चाहिये मगर यह कहते हैं कि दौलत को बांटना चाहिये। इसको करने से पहले, मजदूरों को अच्छी तनख्वाह मिलने के पहले हम को पैदा करके बताना पड़ेगा। बम्बई में जो कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल हो गई है इस विषय में मैं जानता हूं कि भारत सरकार ने इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया है जैसे कि हमारे

मजदूर लोग कहते हैं कि सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर बैठी है। मेरा कहना यह है कि जहां तक मजदूरों के हितों का प्रश्न है, जहां तक उनकी गरीबी दूर करने का सवाल है कभी भी कांग्रेस सरकार, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया। और यही कारण है कि अभी हाल ही में जो हमारे माननीय मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है और जो उनके लिए सुविधायें दी हैं वे इस बात को बताती हैं कि जहां तक सरकार का प्रश्न है, जहां तक हमारी पार्टी का प्रश्न है वह गरीबों के लिये मजदूरों के लिये जो कुछ भी देना होगा, जो भी उनके लिये करना होगा उसको करने से पीछे नहीं हटती। परन्तु मजदूरों को श्रम के लिए प्रेरित करना जितना भी संभव हो सके हमें उनमें इस प्रकार की भावना का प्रसार करना चाहिए।

बार-बार पूंजीवाद का नाम लेने से बार-बार समाजवाद का नाम लेने से न तो समाजवाद आता है, न पूंजीवाद मिट सकता है। आपने कभी चर्चा की कि राजाओं-महाराजाओं के प्रिवीपर्स को हमने समाप्त किया। वह एक संकल्प था उस संकल्प को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी आगे आई। परंतु आपकी पार्टी जो विरोध पक्ष में थी उन लोगों ने इसका विरोध किया, यही कारण है कि प्रिवीपर्स का मामला उस समय फेल हो गया, पास नहीं हो सका। तो आप यहां पर जितनी बातें कर रहे हैं ये केवल अपने मन को समझाने के लिए अथवा अपनी पार्टी और कार्यकर्त्ताओं को बतलाने के लिये आप लम्बा चौड़ा भाषण देते है, बातें करते है। परन्तु जब काम करना होता है जब व्यवहार की बात होती है, आचरण की बात होती है तो उससे आपका कोई संबंध नहीं रहता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के अमेंडमेंट लाने के पूर्व किसी प्रकार के संशोधन प्रस्तावित करने के पूर्व आप लोग खुद अपने मन में सोचें कि कहां तक आप इस देद को आगे ले जाना चाहते है। आप कभी भी बैठकर कोई भी मतभेद दूर कर सकते है। विरोध पक्ष सरकार के साथ बैठ कर कोई भी जो इस तरह के मतभेद हो दूर कर सकता है और लोकतंत्र में मतभेद होते हैं। अगर मतभेद नहीं होते तो लोकतंत्र रहा नहीं, वह तानाशाही हो जायेगा। मतभेद से किसी को इन्कार नहीं है परन्तु मतभेद एक बार किसी चीज का निर्णय लेने से पहले दूर हों।

चुनाव हो, चुनाव में जो भी पार्टी विरोधी पार्टी जीतकर जाती है तो हमें उसको बराबर स्वीकार करके उसको मौका देना चाहिये कि जिन प्रामिसेस को लेकर उसने वोटर को प्रसन्न किया, जनता के लिये जो वाक्य रखे, उसको उस काम को करने का मौका हो। परंतु हमारे अधिकार केवल एक दूसरे के कपड़े खींचना नहीं है। सरकार को छालेदार करने में, उसकी आलोचना करने में, जनता में झूठी बातें करने से एक खराब वातावरण बनता है। मैं नहीं मानता आप कितने ही संशोधन कर डालें उससे कभी भी आप अपने देश का उद्धार कर सकेंगे।

आज भारत का संविधान संसार के जितने भी राष्ट्र है, जितने भी प्रगतिशील लोकतंत्र राष्ट्र है उन राष्ट्रों के संविधान से किसी भी तरह कम नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो भी हमारे सामने संविधान है, जिन्होंने इस संविधान को बनाया था, बराबर इस बात की उनकी कोशिश थी कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी सुख और सुविधा से रह सके। इसके लिये उन्होंने संविधान में संसार की

[श्री नन्द किशोर भटट]

अच्छी से अच्छी बात को रखा । परंतु हमने अपने आचरण के द्वारा यह सिद्ध करके रख दिया कि हम इस प्रकार के आचरण के लिये तैयार नहीं हैं । जिस विषय पर चर्चा चल रही है, वह विषय ऐसा है कि आप कितना ही बोलने चले जाइये । मुझे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है । मैं माननीय झा जी का विरोध करूंगा । जिस भावना से प्रेरित होकर यह संशोधन उन्होंने रखा है अगर संशोधन करने से ही यह संसार स्वर्ग बन सके तो हम बराबर उनके साथ है । परंतु हम जानते हैं कि केवल बातों से या कागज को कलम फेंक देने से काम नहीं चलता है। तो यह देश तभी आगे बढेगा जब हम महात्मा गांधी का रास्ता अख्तियार करेंगे । जो कार्यक्रम और रूप रेखा देश को आगे बढाने के लिये पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखा और उद्योग तथा अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया उस पर जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, जब हम इसको और मजबूत करें ।

मैं श्री हुकमदेव नारायण यादव जी से सहमत हूं कि जहां पर कुटीर उद्योग हैं उनको मदद देनी चाहिये। बैंकों के राष्ट्रीय करण के बाद आज यह संभव हो सका है । जो लोग उद्योग करना चाहते हैं, जो जो भी आगे आना चाहते हैं उनको सब प्रकार की सहूलियत दी जायेगी । इन सबके होने के बावजूद भी हम लोग जहां तक पर्लियामेंट का सवाल है, जहां तक आपके संशोधन का सवाल है, हम जिस तरीके से व्यवहार करते है उससे कभी यह देश आगे नहीं बढेगा । समाजवाद कभी आ नहीं सकेगा । महात्मा गांधी का स्वप्न पूरा नहीं हो सकेगा । संविधान अपनी जगह पर है, संविधान में किसी प्रकार की कमी नहीं है । कमी है तो हमारी संकल्प

as on prepage

शक्ति की, जिस संकल्प शक्ति की ओर हमारे पूर्ववक्ता ने इशारा किया । कमी है इच्छा शक्ति की । तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के बिल लाने से देश आगे नहीं बढेगा । आवश्यकता इस बात की है कि हमने संविधान में जो भी प्राविधान देश की जनता के लिये, सर्वहारा के हितों को आगे बढ़ाने के लिये रखे है आईये हम मिल जुल कर उस पर काम करे और उसके बल पर अपने देश को इतना मजबूत करें कि दुनियां को बतलादें कि लोकतंत्र के द्वारा ही यह संसार आगे बढ सकता है। आज आप जानते है। अगर आप दुनियां को नजर उठाकर देखे तो इंगलैंड में जो भी तरक्की आई पहले वहां डैमोक्रेसी आई फिर इंडस्ट्रिल रिवाल्यूशन आया । इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उस के बाद पालियामेंट्री डिमोक्रेसी आई । अमरीका में यह डिमोक्रेसी आई ....

4 p.m.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Are you opposing or supporting the Bill?

SHRI NAND KISHORE BHATT: I am certainly telling my views.

इसलिये भारतवर्ष में जो लोकतंत्र का प्रयोग चल रहा है, मैं आप को आह्वान देता हूं आप सहयोग दीजिये । यह प्रस्ताव पास कर देने से काम नहीं चलेगा, संविधान में काफी प्रावधान है । मैं आप से अनुरोध करूंगा इस बिल को वापस लेकर निष्ठा और श्रद्धा के साथ आगे आयें और हमारे साथ मिल कर काम करें और देश को मजबूत बनाने की कोशिश करें । डा० राम मनोहर लोहिया बहुत बडे विद्वान और विचारक थे, मैं उन के विचारों से सहमत हूं परन्तु मुझे अफसोस है, उनके साथी उनके विचारों की बात तो करते है लेकिन उनकी बातों में और आचरण में जमीन और आसमान का फर्क है ।

मैं फिर अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो यह कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा है इसको वापस ले लें और सच्ची निष्ठा के साथ आगे आयें और देश को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान करें।

SHEI ARVIND GANESH KUL-KARNI: Madam, Vice-Chairman, I was very carefully listening to my good friend, Mr. Bhatt; his intentions particularly his concern for the young ^unemployed, I could fully appreciate. But the way in which he was suggesting the remedies whereby this unemployment can be reduced or the unemployed youth will get more benefits, whether as a part of a dole or by his own arrangement, I was not convinced by his arguments.

Madam, I am thankful to Mr. Shiva Chandra Jha who has brought forward an important Bill. This is an important Bill and it is in everybody's mind as to what will happen to these unemployed youth whether educated or uneducated, especially keeping in view the situation in which the present economic conditions in this country, the cultural traditions of this country have been deteriorating for the last so many years, particularly during the last ten years, with the result that the value systems have reached the lowest point, and how these people can find a respectable person, or a respectable personality or a respectable political party or a system wherein they can pin their faith or can hope for the best in the future. I am myself doubtful because, as I have already mentioned, the economy does not sustain such hopes. I am also doubtful because the value system and the cultural standards have already reached the lowest point and how can the youngsters keep their faith in a political system which we have adopted. I am very much doubtful cibout this.

I would have agreed with Mr. Bhatt—Oh, he has gone away—if an economic solution could have been found for this problem. I am doubtful if the dole system will be useful. I have got my own doubts because we have worked during the last 30 years many system and we have seen in many countries, particularly Egypt, where T had personally gone on some delegation, where President Nasser at that time introduced a system of giving bread to all the population at a fixed price, I think in Tamil Nadu also they had got some scheme like 'one rupee one measure', that such a system made the people lazy and the net effect in Egypt I could find was that the people became lazy. Here also, Madam, the same would be the experience, if one were to see the result of various schemes which have been announced, various relief schemes which have been announced by the Government, which have been formulated in the Planning Commission, and one who works at the field level will have the same experience.

I would have liked this economy to grow but unfortunately the position is otherwise. Somebody criticised about the IMF loan, I think it was Mr. Hukmdeo Narayan Yadav. There is nothing wrong in getting loan from any world organisation. Utilisation of t'he loan is the crux of the problem. Now, fortunately the Commerce Minister is here, and I was going to make my point. I am not saying it just because the Commerce Minister is here. Madam, after this new import policy was announced—it is very recently—I wrote to about 700 small-scale entrepreneurs and organisations to know the effect of the new import policy on their products. I have thus collected a large amount of statistics. They say—it is not my view; I am not against this IMF loan or anything— it seems the Government is forced to liberalise the imports and thereby their products have been affected. Since the Minister is here, I can make a reference. I have already sent to him my scheme. I am also putting it before the Industry Ministry's Consttl-tative Committee as to what is hap-

[Shri Arvind Ganesh Kulkarni]

pening to the small-scale sector. I ' only wanted to bring to the notice of Mr. Bhatt. This is one of the ways.

Here also, the Government has announced various schemes for even technologically trained or educated youth. Many schemes are announced, and I do not think any other scheme is available in the world, even in Japan or in the USA, which is comprehensively superior. I think whatever schemes have been promulgated by the Government of India, are quite enough if they are genuinely implemented. If they are properly implemented, no further schemes will be necessary. But the only thing is that they should be implemented properly and in a way so that the entrepreneur does not have to face problems. He is rather encouraged to go in for small industry or big industry or medium industry as he likes. I do not think any other scheme is necessary. It is only the handling of the schemes by the bureaucracy which is creating problems. For that purpose, instead of spending Rs. 70 crores or Rs. 700 crores, if the Government of India applies its mind on how to remove these clutches, and allow youngmen to follow their own pursuits and trades, that will help a long way.

Now, there is an integrated rural development programme. But what is happening at the rural areas? The programme is there; programme is not bad but unfortunately it is connected with local administration which under political influence twists the scheme and ultimately the people are not benefited. And whatever one may shout fdr one employment opportunity for one family, will not result in anything. I think in (Kerala or in West Bengal or some other places, these schemes are working very nicely. Even public distribution system is working well. Maharashtra also has a pride of place in this employment-guarantee scheme, and Maharashtra's scheme is actually a model scheme. But unfortunately during the last one or two years, there also bureaucracy, is playing mischief and even the Collectors who unearthed malpractices in the employment-guarantee scheme are transferred forthwith on political pressures.

Here I would like to draw the attention of the hon. Minister, the Law Minister, that one Mr. Bhatia who was an ideal Collector in Jalgaon was transferred forthwith because he sent a report to the Government that mal-practices are taking place in the imple-mentation of the Employment Guarantee Scheme, that muster rolls have been forged and so on. We, in the Opposition, will go on shouting against you. But actually, we cannot solve this problem of unemployment. Neither you can solve it because your political friends are creating problems for you. Because of this, you also cannot have a proper atmosphere for this purpose. My friend, Mr. Jha's Bill speaks about the employment guarantee scheme and it also mentions a dole of some Rs. 100 or Rs. 200 in regard to this. I will ask you, Madam. You are also a doctor now. Not that you are only a graduate. Suppose, you are to pay capitation fee in respect of your son or your daughter, what will you feel? Mr. Gundu Rao in Karnataka has made a commercial market of this. Recently, there was a very good article in the 'Sunday'. What does it say? It has been mentioned therein that many new colleges have been allowed on this basis, many new colleges are being allowed by Mr. Gundu Rao. Does it evoke any ideal? Does it keep any ideal before the youth of this country? Similarly, Madam, it is not only this capitation fees. The problem is that the youth are very much restless and everybody knows it. I am moving at the field level. Everybody who is a Member of this House and a Member of the other House is a field worker. Mostly, we are field workers. We know it. The youth, not only in the rural areas, but in the urban areas also, are becoming restless and for this purpose, some type of an ideal has to be created by the ruling party,

by the Opposition parties and by all the political parties, whereby we shall create a new enthusiasm among our youth, whether it is the rural youth or the educated youth, and encourage them to undertake some type of productive activities. I have mentioned about the employment guarantee scheme. Similarly, there are medium irrigation schemes which can be implemented. The biggest difficulty, it sesms to me, is this. My friend, Mr. Bhatt—he has already left; I cannot help it—was giving the example of how his Government and Madam Prime Minister are concerned with this. I am also aware that Madam Prime Minister is concerned with this. Anybody who wants that a socialistic pattern of society should be established in this country will be concerned with this. But when I lay my hands on a book, the 47th Report of the Committee on Public Undertakings, what does it say? It is not only Mr. Gundu Rao. Now, I am not mentioning Mr. Antulay. Do not get afraid and scared also. Because, I think, Mr. Antulay, for the present...

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Antulay is over.

SHRI ARVIND GANESH KUL-KARNI: Nobody knows whether Antulay is over or not. If the party requires him to come back, what can you do? I am not mentioning Mr. Antulay now. But, I would only like to draw your attention to page 27 of this report. I do not want to quote for want of time because I will take more time. But the pertinent point seems to me, as it has been mentioned here:

> "While purchase of HSD on long-term basis was made from SNE, Moscow, at US $325.46 per MT, the price at which 512,155 tonnes of the product was purchased from Kuo Oil, Hong Kong, fthrough Hindustan Monark, New Delhi) in the same period was US $350.65 per MT. The Committee were informed that the Moscow agreement was signed on 6 February, 1980, on variable price basis whereas the other agreement was signed on 29 February, 1980, on fixed price basis for the whole year."

It has been found that the Minister went out of the way and obliged this Kuo Oil of Hong Kong and gave them the benefit and it has also been admitted that the Indian Oil Corporation lost about Rs. 10 crores. It has been admitted by the IOC that the country-lost about Rs. 10 crores.

The file concerning this was absent from the Public Undertakings Committee. The Committee even threatened them, because their term was expiring on the 30th April, 1982. Mr. Minister, please take note of it. File No. P-20 was missing from the Ministry for full two months. And the Personnel Assistant to the Petroleum Minister—it was Mr. Veerendra Patil at that time—by name Channavee-rappa confesses that he handed over the file to the Special Assistant to the Prime Minister and the file did not corne back. On the last day. on the 28th or 29th April suddenly the file comes back; it is traced. It is found that the Minister gave a directive to purchase, throwing to the winds all the norms of Government purchases by tenders. This was a fixed price contract to oblige Kuo Oil of Hong Kong. Please take note and inquire into this and give us the facts. Mr. Jha was asking for Rs. 70 crores. This one transaction has collected many many crores. And Mr. Bhatt was talking about idealism, etc. Mr. Kamal Nath had been connected here. I did not want to mention it. It is mentioned that he was attending the meeting. I thought he was a member of that Hindustan Monark, but I do not know. You will have to inquire. There is one Mr. Jain. One can't say how many Jains and how many Kamal Naths are there, or who is who. And God knows how a third person was attending the Minister's meeting with the Secretary. I do not know. But it goes to the credit of Mr. Vohra and Mr. Loveraj Kumar who placed a

[Shri Arvind Ganesh Kulkarni]

note before Mr. Sethi, who was then the Minister, that this procedure should not be flouted. *(Time bell rings)* Madam, I have done. What I wanted to submit was, having said all this, all political parties—it is not only your ruling party—and political personalities have to come to certain minimum standards to create a model, a respectable model, before the educated and uneducated youth. Otherwise there will be corruption at the highest level. And the fact that file No. P-20 is absconding for two months in the Prime Minister's secretariat is something ridiculous and condemn-able, something to be ashamed of.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Madam Vice-Chairman, I rise to support the Bill. The Bill seeks to introduce an amendment for guarantee in the right to work to the youth of the country and to give some sort of an unemployment relief. Madam, the problem of unemployment is a very peculiar problem in our country. If we look at the number of unemployed, we will find that the number of unemployed youth is actually reaching a formidable figure. This is demoralising the workers, demoralising the youth, creating frustration among them and in every State, the Government is embarrassed with the problem of unemployment. If we look at the Employment Exchanges ■whether in the big cities or in the small cities, we will find that every Employment Exchange is crowded ■with big queues of unemployed persons seeking to register their names. And after their names are registered, they wait for five to ten years, or «ven more than that. But despite •waiting for even 10 to 15 years, they find that all their hopes are belied. This is the position of the youth of our country. We find that our boys go to schools and colleges and come out of them but later on do not find any employment. Even when they study in the schools and colleges, they feel their future is bleak and dull; they know very well that after coming out of the schools and colleges they will not be able to find any employment. So, frustration sets in them even when they are in the schools and colleges. They suffer from demoralisation and frustration. As a result, the standard of education is going down day by day. Unless there is a future for the youths of our country, they feel why should they read? So the fall in the standards of education is also influenced by the problem of unemployment in our country. So this problem of unemployment shouia ue looked into from all these aspects. It has become a social problem in the present-day India. That is why the Bill seeks to remedy this disease and I support this Bill.

Secondly, for creating employment opportunities, our country should go in for both heavy and small scale industrialisation. Certain industrialisation is there. But what we find is that most parts of the country still remain basically agrarian. In some parts of the country there is industrialisation. If there is industrialisation in most parts of the country, most of the youth can be accommodated and employed there. I feel without creating industrialisation in a big way, without creating industries evenly throughout the country, in all the States equally, the youth cannot be accommodated properly in various States. Now, what is happeing because of the dearth of employment opportunities? In some places we find the obnoxious theory of sons of the soil coming up. This theory means one young man from one State cannot get employment in another State. This theory is being spread to this extent that one young man of one district cannot get employment in another district of the same Stare. The man of one district cannot go and register himself in the employment exchange of another district. Because of this there has started a division among the youth, there has started a division in the working class. This

pernicious theory of sons of the soil is the result of the tremendous unemployment in our country,

For fast industrialisation of the country basic land reform$_s$ are necessary. What is the main ailment of our country's industrialisation? We find that our industries are suffering from underutilisation of their capacity. The industries are not in a position to utilise their capacity. If they produce more they won't find a market. It means the capacity to purchase of the rural people of our country is low, is very low. If the cloth mills produce more cloth, if more consumer goods are produced, the people of our country are not in a position—the bulk of the people— to buy the cloth Or the consumer goods. As a result our industries are suffering from underutilisation. So, these are some of the problems for the industrialisation of the country. These things have to be laoked into by the Government if w.e really want to solve the problem of unemployment.

And then, even if industrialisation is advanced rapidly, it will take some time to accommodate and absorb all the unemployed youth in some gainful employment. So, for the time being and temporarily, the scheme of •unemployment relief should be introduced in every State. Every State should take up the unemployment relief scheme. In some States this scheme is in operation. In West Bengal after the coming into power of the Left-Front Government, they have introduced the unemployment relief scheme and we find that in Bengal the scheme is very much welcomed and hailed. Some may say it is non-productive, unproductive, way of spending money. Yesterday the Finance Minister ridiculed the scheme of unemployment relief. He said that it was a populist method of satisfying .tile people. No, it is not a populist method. In the Western countries thi$_s$ sort of relief is there. In Socialist countries employment is guaranteed in the Constitution. In Great Britain unemployment relief scheme is there.

In Great Britain you cannot say that they are following any populist method. Leave aside the socialist countries, even in capitalist countries some sort of employment guarantee is there. In West Bengal the scheme of unemployment relief is working well. If this is followed in other States and unemployment relief is given to the youths, they can be employed in some productive work. For instance, their services can be utilised in the adult literacy campaign or in some other social services so that they will not have the feeling that they are getting some doles from the Government. They will feel that they are doing something good for the society. In this way unemployment relief scheme can be put into practice everywhere.

Therefore, I feel this is a very important and useful amendment to our Constitution and I support the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): Shri Suraj Prasad. You have only five minutes because at 4.30 we are taking up the Calling Attention.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदया जी. . .

उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला] : आपको सिर्फ पांच मिनट मिलेंगे आज बोलने के लिये क्योंकि 4.30 बजे कालिंग अटैन्शन शुरू कर रहे हैं।

श्री सूरज प्रसाद : महोदया, जो अभी झा जी ने प्रस्ताव पेश किया है, संविधान में संशोधन का, मैं उसका समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं उनका संविधान के अन्दर प्रावधान होना चाहिये लेकिन इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना

[श्री सूरज प्रसाद]

है उसमें भारत को एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में कहा गया है । जब भारत को एक समाजवादी राष्ट्र मान लिया गया तो उसकी प्रस्तावना के मुताबिक भारत में काम होना चाहिये । लेकिन भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है वह नान जूडीशियल है, उसको कानून के अन्दर किसी कचहरी में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं । इसलिये देश के सामने जो बेकारी की समस्या है, वह समस्या काफी गंभीर है

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए ।]

और देश के अन्दर जो अभी आर्थिक व्यवस्था है उस आर्थिक व्यवस्था की यह सबसे बड़ी गंदगी है । उस गंदगी को दूर करने के लिये जाहिर है कि सब तरह के कदम उठाने की जरूरत है ? आर्थिक कदम उठाने की जरूरत है, राजनैतिक कदम उठाने की जरूरत है । लेकिन आर्थिक और राजनैतिक कदम उठाने के साथ ही साथ भारत के संविधान के अन्दर अगर कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया तो जाहिर है तो उसका कोई लाभ देश की जनता को, देश के जो बेकार लोग है, उनको नहीं होगा । अभी जो प्रावधान हमारे संविधान के अन्दर है, जो प्रस्तावना है और प्रस्तावना के बाद जो दूसरे प्रावधान हैं जिनमें कहा गया है कि सब कानून के सामने बराबर है, लेकिन व्यवहार में उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है । प्रस्तावना नान-जूडीशियेबल हो गई है, अगर किसी धारा में लिखा गया है सबको काम दिया जाय और कहीं डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कहा गया है कि राज्य इसके लिये प्रयास करने की कोशिश करें और काम की गारंटी करें लेकिन क्योंकि ये बातें जूडीशियेबल नहीं है, इसलिये इनको हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते और रिलीफ नहीं पा सकते हैं । ऐसी अवस्था में भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी राष्ट्र की बात कही गई है, उस दायरे के अन्दर अगर कोई रिलीफ पाना चाहता है तो भारत के संविधान में उसके अनुरूप संशोधन की जरूरत है और उसी के अनुरूप झा जी ने इस संशोधन को पेश किया है । इसीलिये मैंने आपसे कहा कि मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं क्योंकि अगर आपने समाजवादी राष्ट्र देश को मान लिया है, यह देश एक समाजवादी राष्ट्र है और हम को उसी दिशा में निर्माण करना है । जब जरूरत इस बात की है कि उसके अनुरूप देश में काम होना चाहिये, उसके अनुरूप काम होना चाहिये लेकिन उसके मुताबिक कोई ऐसा हम काम देश के अन्दर नहीं पाते हैं । इसलिये हम यह कहना चाहते हैं कि जब समाजवादी राष्ट्र है तो कोई एक ख्याली पुलाव समाजवाद नहीं है वह एक राजनीतिक विचारधारा है वह एक सामाजिक विचारधारा है वह एक सामाजिक विचारधारा है वह एक दार्शनिक विचारधारा है और राजनीतिक विचारधारा के अन्दर समाजवाद के अन्दर हर आदमी को काम मिलना चाहिये । यह उसका एक मान्य सिद्धान्त है । जिन-जिन देशों में समाजवादी हकूमतें हैं उन तमाम देशों के अन्दर काम पाने का अधिकार संविधान के अन्दर निहित है ।

श्री उपसभापति : आप अपना स्थान ग्रहण करें । यह बहस जारी रहेगी । अब कालिंग अटेंशन लिया जाता है ।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Serious situation arising' out the prolonged strike in textile mil's in Bombay, resulting' in loss *ot* production and hardship to workers.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Sir, I beg to call